टंकण यंत्रों, टंककों एवं आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है। यह संख्या हिन्दी में प्रशिक्षित टंककों एवं आशुलिपिकों की संख्या के अनुरूप में है। सरकार इस संख्या को "क" क्षेत्र में हिन्दी में निर्धारित काम को देखते हुए बढ़ाने के लिए यथा संभव प्रयत्न कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है :—

राजभाषा विभाग इलेक्ट्रानिकी विभाग के साथ समन्वय कर विभिन्न कार्यालयों में द्विभाषी कंप्यूटर एवं साफ्ट-वेयर के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस समय बाजार में बहुत से शब्द संसाधकों के पेकेज उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य हो सकता है। जहां तक कि ऐसे प्रोग्राम लिखने की भी सुविधा उपलब्ध है, जिन पर कि द्विभाषी रूप में आंकड़ों का विश्लेषण हो सकता है। देवनागरी में इलेक्ट्रानिकी उपस्करणों के विकास तथा प्रयोग की समीक्षा इस विभाग में एक मंत्री-स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। द्विभाषी टेलीप्रिंटर के विकास के लिए राजभाषा विभाग ने हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर को दस लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए हैं। विभाग ऐसी संस्थाओं तथा कार्यालयों के प्रति विशेष ध्यान दे रहा है, जो इन उपकरणों का अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं। टंककों का अनुपात "क" क्षेत्र में मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और अन्य कार्यालयों के लिए यह 50 प्रतिशत है। इसी तरह यही अनुपात 'क' क्षेत्र के आशुलिपिकों पर भी लागू होता है। टंकण यंत्रों के संबंध में भी यही अनुपात लागू होता है। पहला अनुपात केवल नये खरीदे गये यंत्रों पर ही लागू होता था, लेकिन वर्तमान आदेशों में अनुपात कुल संख्या पर लगाया गया है। जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। आशुलिपिकों के अनुपात में कमी को 31.3.1990 तक पूरा किया जाना है तथा टंककों के अनुपात में कमी को 31.3.1989 तक भरना होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित कार्यालयों में 1.4.1988 से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हिन्दी में भेजे गये पत्रादि के उत्तरों के मसौदे हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे।

टिप्पण और आलेखन के लिए "क" क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता 50 हजार शब्दों से घटा कर 20 हजार शब्द कर दी गई है। इससे अनेक ऐसे व्यक्तियों को देवनागरी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिनके लिए 50 हजार शब्द लिखना कठिन था।

Opening of New Branches of Banks

797. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have a proopsal to open new branches of nationalised banks in the country;

(b) if so, what is the number of such new branches propsed to be opened in different States in 1988-89 financial year (Bankwise); and

(c) how many branches of those banks have been opened in different States as on 30th June, 1987?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) Opening branches by commercial banks is ongoing process. On the basis lists of identified centres receiv from the State Governments, Ri

has allotted upto 31.12.1987, 5365 centres conforming to the norms laid down in the current Branch Licensing Policy to commercial banks and regional rural banks. Out of these 5365 centres, banks have opened 1292 branches in different States of the country upto 31.12.1987. RBI has advised the banks that branches at the allotted centres should be opened in a phased manner during the remaining period of the current Policy. Annual targets for openig branches have not been prescribed. As such, it would not be possible at this stage to indicate the number of new branches that will be opened by banks during 1988-89 in different States.

Income-tax raids

798. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Income-tax Department has conducted raids during the last six months and found undisclosed wealth in different States;

(b) if so, what is the amount of wealth found from the raids during the last six months; and

(c) what action Government have taken against the persons evading income-tax?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) and (b) Yes, Sir. The Income-tax Department conducted 4446 searches in various parts of the country from August, 1987 to January, 1988. These searches resulted in the seizure of *prima facie* unaccounted assets to the tune of Rs. 69.71 crores.

(c) Appropriate action under the Direct Taxes Acts is taken in all these cases.

Setting up of a National Housing Bank

799. SHRIMATI KRISHNA KAUL:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to set up a National Housing Bank to improve availability of housing finance;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when it is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Yes, Sir.

(b) National Housing Bank is being set up under National Housing Bank Act, 1987 as an apex level housing finance institution with an initial capital of Rs. 100 crores to be fully subscribed by the Reserve Bank of India. It would promote and develop specialised housing finance institutions both at regional and local levels. It will regulate working of housing finance institutions and coordinate their activities as also of other agencies in housing. The extension of financial support to housing finance intermediaries will also be one of the functions of the Bank.

(c) Preparatory work for establishing the National Housing Bank has already been initiated.

Seizure of Narcotics

800. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the estimated value of the narcotics seized at various